प्रदेश में अतिपिछड़ा वर्ग विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

1 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अतिपिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति दी। यह राशि एमबीसी विकास कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 'देवनारायण अनुप्रति योजना' के लिये 1.50 करोड़ रुपए, 'देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति' के लिये 8 करोड़ रुपए, 'देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति' के लिये 135 करोड़ रुपए, 'देवनारायण गुरूकुल योजना' के लिये 17.50 करोड़ एवं 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना' के लिये 20.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा एवं जयपुर के विराटनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 37.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- इनके अलावा अलवर के उमरेण, टोंक के निवाई तथा जयपुर में मानसरोवर व प्रतापनगर में देवनारायण छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये 11.20 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में एमबीसी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rs-231-crore-sanctioned-under-various-schemes-in-the-extremely-backward-classes-development-fund-in-the-state